



गिरिराज

हिमाचल की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण

ISSN 2454-9738

डाक पंजीकरण संख्या

एच.पी./42/एस.एम.एल. 2018-2020
साप्ताहिक आर.एन.आई. 32195/78

इस अंक में

कृषि एवं बागबानी-5, धर्म-संस्कृति -6-7,
कहानी-8, महिला/बाल/स्वास्थ्य-9, पहाड़ी-10

वर्ष 43 अंक 31

शिमला, 5 मई, 2021

हर बुधवार को प्रकाशित

मूल्य : एक प्रति 5.00 रुपये वार्षिक 250 रुपये

आजीवन 2500 रुपये

website:himachalpr.gov.in/giriraj.asp

सामुदायिक भोज पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

प्रदेश में अभी तक 16.65 लाख लोगों को मिल चुकी कोरोना खुराक

केंद्र से अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति का आग्रह



मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर शिमला में कोविड-19 के प्रबंधों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए

प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत वैगाहिक और अन्य सभी प्रकार के आयोजनों में सामुदायिक भोज (धाम) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए गत दिनों शिमला में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में तीव्रता से हो रही वृद्धि चिंता का विषय है। प्रदेश सरकार इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और सरकार ने कई कठोर निर्णय भी लिए हैं। सरकार ने विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने

बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए प्रभावी तंत्र

सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्यादा कोविड प्रभावित जिलों जैसे कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सोलन, ऊना और सिरमौर के अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में कोविड के सैम्प्ल लेने के कार्य में

की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर भी 10 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में पांच कार्य दिवस होंगे और 10 मई तक कार्यालयों में श्रेणी तीन व चार की 50 प्रतिशत उपस्थिति

तेजी लाई जाएगी और रिपोर्ट भी कम समय में उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को 14 दिनों तक

जाएगी। अभी तक 16,65,481 लोगों को कोविड की सुरक्षा दी गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों पर निगरानी के लिए चार कमेटियों का गठन किया गया है।

लॉजिस्टिक कमेटी में राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक अर्दिम चौधरी को संयोजक सदस्य नियुक्त किया गया है।

यह कमेटी ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के अर्डर की समयबद्ध उपलब्धता, जिले में मरीजों के लिए ए ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति और अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी निभाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एसएसओ डॉ. राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कोविड-19 मरीज/ एम्बुलेंस प्रबंधन कमेटी जिला स्तर (शेष पृष्ठ 11 पर)

प्रधानमंत्री की पुरस्कृत पंचायतों को बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 2021 के अवसर पर गत दिनों वर्षुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की पुरस्कार विजेता पंचायतों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक द्वारा गांव में सर्वेक्षण और मैरिंग (एसवीएमआईटीवीए) स्वामित्व योजना का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार विजेता पंचायतों के बैक खातों में पुरस्कार राशि भी हस्तांतरित की और एसवीएमआईटीवीए योजना पर आधारित कॉफी टेबल बुक जारी की। प्रधानमंत्री ने 5002 गांवों में लगभग 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का भी शुभारंभ किया। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नियोजन के लिए एक स्टीक भूमि रिकॉर्ड तैयार करना और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना, ग्रामीण भारत के नागरिकों को क्रष्ण और अन्य वित्तीय लाभ हासिल करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने के लिए सक्षम करके (शेष पृष्ठ 11 पर)

पंचायतों के काम-काज पर केन्द्र सरकार की मोहर

योगराज शर्मा

लोकतंत्र की बुनियादी इकाइयों पंचायतों के कामकाज पर केन्द्र सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाली देश की चुनिदा पंचायतों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने वर्षुअल माध्यम से पंचायतों को इन पुरस्कारों से नवाजा। स्मरण रहे कि हिमाचल प्रदेश कोई-पंचायत पुरस्कारों में राष्ट्रीय स्तर पर पर

गया है। इनमें जिला परिषद बिलासपुर, पंचायत समिति देहरा, पंचायत समिति नादौन, जिला कुल्लू

की कुंगश व मंगलौर पंचायत कांगड़ा जिला की घोड़ीथ, हमीरपुर की किटपल और सिरमौर जिला की लाणा बालटा पंचायत को बेहरीन कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ उन्हें सम्मान

प्रधानमंत्री ने ई-पंचायत पुरस्कारों से नवाजी पंचायतें

'स्वर्ण जयंती नारी संबल' नई पहल

राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के हित में अनेक कदम उठाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। एक अप्रैल, 2021 से राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में 40 हजार अतिरिक्त लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पैशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा वरिष्ठ महिलाओं के लिए विशेष अतिरिक्त, सरकार द्वारा वरिष्ठ महिलाओं के लिए विशेष योजना 'स्वर्ण जयंती नारी संबल' शुरू की गई है।

राज्य सरकार ने अपने पहले ही निर्णय में राज्य के अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा पैशन की पात्रता की आयु सीमा को बिना किसी आय सीमा के 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है। सरकार का यह निर्णय पिछ्डे व कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है।

सरकार ने जहां समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा पैशन में बढ़तीरी की है वही कमजोर व पिछ्डे वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की है।

वर्तमान राज्य सरकार ने अपने गत तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान सामाजिक सुरक्षा पैशन के 1,63,607 नए मामले स्वीकृत किए हैं। जिनमें वर्ष

2018-19 में 97,139, वर्ष 2019-20 में 23,442 और वर्ष 2020-21 में 43,026 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य में कुल 5,77,604 पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैशन प्रदान की जा रही है।

४ संजय सैनी

राज्य सरकार ने एक अप्रैल, 2020 से विधायाओं तथा दिव्यांगजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पैशन को 850 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह किया है। 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के पात्र पैशनरों तथा 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगजनों को राज्य सरकार 1500 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पैशन प्रदान कर रही है।

वरिष्ठ महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पैशन का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना भी शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पैशन प्रदान की जाएगी। इससे राज्य की लगभग 60 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना पर भी राज्य सरकार लगभग 55 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पैशन प्रदान होने जाएगी। इससे राज्य की लगभग 60 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी।

महिलाएं लाभान्वित होंगी।

सुरक्षा पैशन का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना भी शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के एक हजार रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पैशन प्रदान की जाएगी। इससे राज्य की लगभग 60 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना पर भी राज्य सरकार लगभग 55 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पैशन से 5.78 लाख व्यक्ति लाभान्वित

हिमाचल प्रदेश ने अपने पूर्ण राज्यत के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तथा प्रदेश सरकार ने इस वर्ष को पूर्ण राज्यत स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने अपने बजट 2021-22 में 'स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना' शुरू करने की घोषणा की है।

वृद्धावस्था पैशन का लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा, जिनके परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी सेवा की पैशन न मिल रही हो अथवा जो संपन्न वर्ग से संबंध न रखते हों, ताकि पैशन योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

निवासी कमला देवी, केसरी देवी सहित अन्य महिलाओं ने सरकार के इस निर्णय की तारीफ की है। वह कहती हैं 'महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में लिया गया यह फैसला सराहनीय है। समस्त प्रदेश की महिलाएं मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने अपने बजट 1000 रुपये पैशन को बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है।

प्रदेश सरकार ने इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पैशन के तहत बिना किसी आय सीमा के बृद्धावस्था पैशन राशि को बढ़ाकर 850 रुपये, जबकि विधायाओं और दिव्यांगजनों की पैशन को बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है।

70 वर्ष की आय पूर्ण करने के उपरांत पिछ्ले एक वर्ष से वृद्धावस्था पैशन ले रहे बंगाणा उप-मंडल की मुच्छाली ग्राम पंचायत निवासी शक्ति चंद कहते हैं 'सरकार ने वृद्धावस्था पैशन के लिए आय सीमा घटाकर 70 वर्ष की है, जिससे काफी लाभ मिला है। हम मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान सरकार का यह समाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार बनने के बाद

मिल सकेगी तथा महिलाएं सम्मान के साथ अपना जीवन-यापन कर सकेंगी।' इस ऐतिहासिक निर्णय से पहले भी मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर के बेतृत में सरकार बनने के बाद

५ अरुण पटियाल

पहली ही कैबिनेट बैठक में वृद्धावस्था पैशन की आय सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का ऐलान किया था। वर्तमान में 70 वर्ष से अधिक आयु के 2.90 लाख वृद्धजन 1500 रुपये की मासिक पैशन पा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में लगभग 1,63,607 सामाजिक सुरक्षा पैशन के नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2020 तक सामाजिक सुरक्षा पैशन के तहत

विभाग द्वारा चयनित 471 स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक शुक्रवार को प्राप्त: 9.30 से 11.30 के मध्य साप्ताहिक योग दिवस शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25,872 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं।

विभाग द्वारा स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,712 विद्यालयों को अपनाया गया है। इन विद्यालयों में विभाग विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, दैनिक जीवनशैली, भोजन के पोषण, सामाज्य बीमारियों और आयुष के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग सम्बन्धी जागरूकता प्रदान कर रहा है। इस प्रकार कहना है कि सरकार की पैशन जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई है तथा मुश्किलों कम हुई हैं। साथ ही बुद्धिमत्ता अपनाकर आयुषपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

विभाग द्वारा स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,712 विद्यालयों को अपनाया गया है। इन विद्यालयों में विभाग विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, दैनिक जीवनशैली, भोजन के पोषण, सामाज्य बीमारियों और आयुष के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग सम्बन्धी जागरूकता प्रदान कर रहा है। इस प्रकार योग एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करने में विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार ने जीवन आयुष संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए अनुदान प्रदान करने के साथ-साथ अन्य आयुष संस्थानों के माध्यम से योगियों को प्रदान की जाने वाली दवाइयों की खरीद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक आयुष मंत्रालय द्वारा विभाग को 57 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्रों को आयुष उपलब्ध कराई जा रही है।

योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का अभिन्न अंग है। वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस भी विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर लेकर उपमण्डल स्तर तक मनाया जाता है। आयुर्वेद

वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में कारगर साबित हो रही आयुर्वेदिक पद्धति

की लोकप्रियता का अन्दाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वर्ष 2019-20 में कुल 42 लाख 7 हजार 504 रोगियों में से 41 लाख 9,559 बहिरंग रोगियों और 9,745 अंतर्गत रोगियों ने अपना उपचार आयुर्वेद पद्धति से करवाया है।

कोरोना महामारी के दृष्टिगत आयुर्वेद विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले मधुयोगियादि कषाय (काढ़ा) का भी वितरण किया जा रहा है। यह काढ़ा कोरोना योद्धाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। अब तक इस काढ़े के लगभग 2.6 लाख रुपये की राशि वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। यह काढ़े के लगभग 1,63,607 सामाजिक सुरक्षा पैशन के नए मामले स्वीकृत किए गए हैं।

रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा प्रदेश के आयुर्वेदिक अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्डों के माध्यम से चिकित्सा बीमा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

खेती के लिए विभिन्न कृषि जलवायी क

राज्य सरकार कोविड से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने को पूरी तरह से तैयार : मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए।

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2021 के अवसर पर गत दिनों शिमला से वर्षुअल माध्यम से राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग करें और संबंधित पंचायतों में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की सहायता करने के अतिरिक्त लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए भी प्रेरित करें।

श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि आज राज्य के लिए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि इस महामारी की पहली लहर के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों ने इस महामारी के कारण उत्पन्न संकट में लोगों की सहायता करने में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा जलरूपों को निःशुल्क भोजन, मारक, सेनिटाइजर आदि प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि इस बार वायरस का प्रसार अधिक तेज और ज्यादा घातक है जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका और बढ़ गई है। उन्हें अपनी संबंधित पंचायतों के लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने ने कहा निर्वाचित प्रतिनिधियों को वायरस के खिलाफ

तीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने में भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि वायरस से खुद को बचाने के लिए यहीं एक प्रभावी रस्ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति काफी चिंताजनक है लेकिन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

* ई-पंचायत में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर पंचायती राज विभाग को बधाई * मण्डी, हमीरपुर व ऊना में तीन टेलीमेडिसिन केन्द्रों का शुभारम्भ

क्षेत्रोंकि राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

उन्होंने कहा कि राज्य में विस्तरों व ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि अपनी-अपनी पंचायतों में सभी विकासात्मक परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें। वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य में 412 नई पंचायतों का गठन किया है जिसका उद्देश्य पंचायतों को अधिक प्रतिनिधित्व देना है। उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने इसमें से 200 कोड रूपये पंचायतों के लिए जारी कर दिए हैं। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि अपनी-अपनी पंचायतों में सभी विकासात्मक परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें। वर्तमान राज्य सरकार ने राज्य में 412 नई पंचायतों का गठन किया है जिसका उद्देश्य पंचायतों को अधिक प्रतिनिधित्व देना है। उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1992 में

देश में 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को सशक्त बनाने और पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने से आग्रह किया कि वे अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के घरों का दौरा करें और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने के लिए प्रेरित करें।

श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए धन कोई कमी नहीं है। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों में पंचायतों के लिए 1600 करोड़ रुपये का बधाई दी। उन्होंने वित्त आयोग ने राज्यों में वित्त आयोगों के लिए 1600 करोड़ रुपये का बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने उन्ना जिला के

थानाकालां, मण्डी जिला के थुनाग और हमीरपुर जिला के आवाहदेवी में तीन टेलीमेडिसिन केन्द्रों का वर्षुअली शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सहायता सिद्ध होगी।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री श्री अनुग्रह ठाकुर ने कहा कि टेलीमेडिसिन सेवाएं लोगों को बेहतर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को अपने घर द्वारा के नजदीक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग का बेहतरीन उदाहरण है।

कांगड़ा, ऊना, सिरमौर व सोलन में रात्रि कपर्यू

कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल मध्य रात्रि से 10 मई तक यात्रा 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कपर्यू लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।

राज्य में आने वाले सभी आगन्तुकों को 72 घंटों के भीतर आरटीपीसीआर परीक्षण अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोविड आरटीपीसीआर परीक्षण नहीं करवाया है तो उसे अपने निवास स्थान पर 14 दिन तक होम व्हाइटीन रहना होगा। उनके पास घर आने के 7 दिन के बाद स्वयं परीक्षण करवाने का विकल्प भी होगा और यदि परीक्षण नेगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होम व्हाइटीन में रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्र में मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-विरेशों को प्रभावी रूप से लागू करने में शामिल होंगे और उनके पास उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके।

बैठक में स्थानीय स्तर पर विशेष कार्यदल गठित किए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इन दलों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-विरेशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

निर्धन परिवारों को दो माह का निःशुल्क अनाज

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का यह सराहनीय निर्णय है जिससे प्रदेश के निर्धन परिवार भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संकट में प्रधानमंत्री के बेतृत्व में देश के हर वर्ग को सरकार की ओर से हरसंभव सहायता प्राप्त हो रही है।

ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का मूल्यांकन करने के निर्देश

राज्य में बे-मौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण फसलों और फलों को हुए भारी नुकसान की समीक्षा के लिए निःशुल्क पांच-पांच किलो अनाज में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संकट में प्रधानमंत्री के बेतृत्व में देश के हर वर्ग को सरकार की ओर से हरसंभव सहायता प्राप्त हो रही है।

श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लगभग सभी जिलों में बे-मौसमी बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश से सेब, गेहूं और मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जो चिंता का विषय है।

उन्होंने उपायुक्तों को यह भी निर्देश

दिए कि वे बीमा एजेंसियों को फसल बीमा योजना के अवधारणा के अन्तर्गत करवाने की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिले में फसलों को हुए नुकसान का मूल्यांकन करें ताकि राहत प्राप्त करने के लिए बुकसान की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा सके।

किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में खोले जाएंगे गेहूं खरीद केंद्र

प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष राज्य में ही गेहूं खरीद केंद्र खोलकर गेहूं खरीद को ज्यादा सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री श्री वीरेन्द्र कंवर ने गत दिनों शिमला में यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और ऊना के किसान अपनी उपज पड़ोसी याज्ञों पंजाब और हरियाणा में बेचने जाते हैं जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनकी सुविधा के लिए प्रदेश में ही गेहूं खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाहौल-स्पिती व किंवौर जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में गेहूं की फसल उगाई जाती है और इस वर्ष लगभग 6701 किंवौर गेहूं की खरीद की जा चुकी है। पांचवा साहिब में 5570, काला अम्ब में 367, ऊना जिला के कांगड़ा में 379.50 व टकर

में हल्के बोझ की दुआ नहीं मांगता मैं तो मजबूत कन्धों की दुआ मांगता हूं।
- अन्नत

लोकतंत्र की बुनियादें पुरस्कृत

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतंत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का सही विकेन्द्रीकरण हो एवं विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर होने के बजाए निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर हो। पंचायती राज संस्थानों को लोकतंत्र की मूल इकाई माना जाता है, जो ग्रामीण भारत के स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। इसलिए यदि पंचायतें सशक्त होंगी तो लोकतंत्र स्वतः सुदृढ़ होगा। ग्रामीण भारत के परिवर्तन के लिए फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। सम्पूर्ण देश में पंचायतों के बीच कई उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता हैं जिन्हें पहचानें और प्रोत्साहित करने की समय-समय पर आवश्यकता रहती है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा जनहित कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। क्योंकि मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का आधार है। हमारी पंचायतें जितनी मजबूत होंगी उतना ही लाभ अन्वित पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। इसी सोच के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं, बुनियादी ढंगे के सुदृढ़ीकरण के साथ उन्हें आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा रहा है। पंचायतों के माध्यम से स्थानीय लोगों को विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सुविधायें मुहैया करवाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार का सदैव यही प्रयास है कि ग्राम पंचायतों के काम-काज में पारदर्शिता, दक्षता लाए जिसके लिए पंचायतों के विभिन्न कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। नवगठित पंचायतों को छोड़कर प्रदेश की सभी पंचायतों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा जा चुका है। लोग विभिन्न सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग कर रहे हैं। इन पंचायतों में परिवार रजिस्टर, जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन पंजीकृत हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश को ई-सुविधा मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में ई-पंचायत के लिए डिलीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दिल्ली से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के आठ पंचायती राज संस्थानों को भी विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। इनमें जिला परिषद् बिलासपुर, पंचायत समिति देहरा, पंचायत समिति नावौन, जिला कुल्लू की कुंगश व मंगलौर पंचायत, कांगड़ा जिला की घोड़पीठ, हमीरपुर जिला की किटपल और सिरमौर जिला की लाणा बालटा पंचायत को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेहतरीन कार्यों के लिए सम्मानित किया है। इसके साथ उन्हें सम्मान राशि भी दी गई है। सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए चयनित जिला परिषद् को 50 लाख, पंचायत समिति को 30 लाख और पंचायतों को 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया है। जिला परिषद बिलासपुर को पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार मिला है। पंचायत समिति देहरा गोपीपुर कांगड़ा व पंचायत समिति नावौन हमीरपुर को भी दीन दयाल सशक्तीकरण पुरस्कार मिला है। जिला कुल्लू के आनी की कुंगश पंचायत व बंजार की मंगलौर को भी दीन दयाल सशक्तीकरण पुरस्कार मिला है। कांगड़ा की ग्राम पंचायत घोड़पीठ भद्रैणा को नानाजी देशमुख और जिला हमीरपुर की पंचायत किटपल को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (जीपीडीपी) पुरस्कार मिला है। जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत लाणा बालटा पंचायत को बाल मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरकार द्वारा दिए गए इन पुरस्कारों का उद्देश्य पंचायती राज से जुड़े लोगों को और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। जो पंचायतें किन्हीं कारणों से इन पुरस्कारों के लिए तय किए गए मानकों में पैछे रह गई हैं वे भविष्य में अपनी पंचायतों में बेहतर विकास कार्य कर पुरस्कार पाने का मौका दोबारा हासिल कर सकती है। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं जिससे न केवल चयनित प्रतिनिधियों का मनोबल बढ़ रहा है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं तथा ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिल रहा है।

कोरोना काल में मीडिया की भूमिका

प्रशासन हमारे लिए पहले भी सहायक रहा है और आगे भी रहेगा। हमें खुद की यह सामाजिक जिम्मेदारी समझ कर कार्य मिल कर करना होगा। काश ! यह बुरा वक्त जल्द निकल जाए। जिन्दगी फिर उसी दर्दे पर लौट आए, हम सब जल्द एक दूसरे से अपने गम और खुशियां बांट पाएं।

मजाक के संदेश आगे बढ़ रहे होते हैं, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को मजाक बना कर बने चुटकुले हम चटखारे लेकर पढ़ते हैं और आगे भेजने में अपनी शान समझते हैं। सोशल मीडिया के पटल को मजाक या तमाशे के पटल न बनाएं। हम सुनागरिक होने का धर्म अपनाएं, यही व्यक्तिगत धारणा है।

अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक

मीडिया की छ. डॉ. अदिति गुलेरी

सरकारों कोई भी हो अगर लॉकडाउन

लगता है तब भी कठघरे में होती हैं, न लगाएं तब भी कठघरे में होती हैं। जब व्यवसाय ठप होते हैं, तो आर्थिक व्यवस्था भी चरमाती है, तब भी हम सिर्फ़ कोसते ही हैं। सार यह है कि हम नहीं सुधरेंगे। परन्तु समाज को जल्द सुधारेंगे। भी प्रिंट मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोगों को सच से अवगत करवाया और उन्हें इस महामारी से सघेत भी किया। वही खबरें पाठकों के समक्ष भी जल्दबाजी में डाल दिए जाते हैं जो भासक रहते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। दूसरा पहलू यही है कि जब जाएं तब भी उसकी लपटें जल्द पहुंचेंगी।

सरकारों कोई भी हो अगर लॉकडाउन

लगता है तब भी कठघरे में होती हैं, न लगाएं तब भी कठघरे में होती हैं। जब व्यवसाय ठप होते हैं, तो आर्थिक व्यवस्था भी चरमाती है, तब भी हम सिर्फ़ कोसते ही हैं। सार यह है कि हम नहीं सुधरेंगे।

सुधारने से पहले हमें अपने आप को और अपनी कार्यप्रणाली को सुधारना होगा। हमें मेलों, ट्वीटों, ऐलियों, भीड़ वाले स्थानों से बचना होगा। हमें इस समय देश का साथ देना है। अगर कुछ बंदिशें लगती हैं, हमें उनका पालन करना है। जिन्हें नौकरी व्यवसाय के कारण निकलना पड़ रहा

है या किसी कारणवश जाना पड़ रहा है वो उनकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन जिनकी मजबूरी हो तब उन्हें बेवजह बाहर निकलना भी नहीं चाहिए।

परीक्षाएं क्या बच्चों की जान से अधिक जरूरी हैं? अगर परीक्षाओं पर रोक लगाई गई, वो बच्चों की जान बचाने के लिए जल्दी थी। जिन निर्णयों का स्वागत होना चाहिए, लोगों को उनमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। समाचार पत्रों ने विज्ञापनों वेब टीवी के माध्यमों से पाठकों, दर्शकों में सकारात्मकता, मनोरंजन का भी ध्यान रखा। कोरोना योद्धा के रूप में इन सभी ने अपना बहुत योगदान समाज को दिया। संपादक, पत्रकार अपनी संपूर्ण टीम के साथ अपनी कलम से समाज को इस बीमारी से बचाने हेतु विचारों, भावों से लड़ते रहे।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट पर भी कोरोना का कहर दिखता रहा। मजदूरों के पलायन से लेकर जलती चिटाएं मन को व्यथित कर गईं। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस विभाग, जल आपूर्ति विभाग, विद्युत विभाग अपने कार्यों में तब मन से लगे हुए हैं। अब पुलिस हमें नहीं रोकेगी, हमें स्वयं लकना होगा। प्रशासन हमारे लिए पहले भी सहायक रहा है और आगे भी रहेगा। हमें खुद की यह सामाजिक जिम्मेदारी समझ कर कार्य मिल कर करना होगा।

काश ! यह बुरा वक्त जल्द निकल जाए। जिन्दगी फिर उसी दर्दे पर लौट आए, हम सब जल्द एक दूसरे से अपने गम और खुशियां बांट पाएं।

जीवन में सफलता का पैमाना केवल अंक ही नहीं

परीक्षा में ज्यादा नम्बर लेकर आगा ही जीवन की राह तय वही करता। इसके साथ-साथ ज्ञान भी जरूरी है। सिर्फ़ अच्छे नम्बर से कोई जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता है। ना ही डिवीजन से। कभी - कभी थर्ड डिवीजन वाला भी आई.ए.एस., डॉक्टर, इंजीनियर, सी.ए.बी.बी.ए. बन जाता है। आपके परीक्षा का नम्बर एक जीवन की नींव बनाती है। कभी - कभी अच्छे नम्बर वाले भी फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। सिर्फ़ मार्क्स जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। आपका मजबूत संकल्प, आत्मविश्वास, मेहनत, आगे बढ़ने की चाही आपकी राह है। ये नम्बर तो जीवन का कठघरा है। आपका असरी ज्ञान, हौसला, आगे बढ़ने की इच्छा, शौक आपके जीवन की राह तय करता है। आपकी सफलता की नींव बनाती है। कभी - कभी अच्छे नम्बर वाले भी फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। सिर्फ़ मार्क्स जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। आपका मजबूत संकल्प,

जीरो बजट प्राकृतिक खेती में गहन कृषि और जैविक खेती के मुकाबले केवल 10 प्रतिशत पानी और 10 प्रतिशत बिजली की जरूरत होती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती में कम लागत लगती है क्योंकि इसमें किसान किसी भी तरह के रसायनों का उपयोग नहीं करते हैं तथा किसान केवल अपने द्वारा बनाई गयी चीजों का उपयोग करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लागत की अपेक्षा ज्यादा मुनाफा होता है।

शून्य लागत प्राकृतिक खेती कृषि का बेहतर विकल्प

किसान अनुकूल वै कंटिपक प्रणालियों की तालाश में सुभाष पालेकर की जीरो बजट प्राकृतिक खेती कृषि समुदाय के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है एक विधि है जिसमें खेत और गांव के बाहर से आदानों की कम या शून्य खरीद के कारण फसलों की खेती की लागत लगभग शून्य है। इसका मतलब है कि किसानों को अधिक उपज प्राप्त करने के लिए महंगे उर्वरकों और कीटनाशकों की खरीद करने की आवश्यकता नहीं है।

इस तरह की आधुनिक खेती के अंतर्गत किसान केवल अपने खेत स्तर पर बनाये गए आदानों जैसे जैविक खाद, कीटनाशक, पौधा धनाशक, कवकनाशक, पौध वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन इत्यादि का प्रयोग करते हैं और किसी भी तरह के रसायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं।

प्राकृतिक खेती के प्रमुख बिंदु

प्राकृतिक खेती में पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत सूरज, हवा और पानी (98.5 प्रतिशत) से आता है तथा बाकी का (1.5-2 प्रतिशत) मिल्ली से मिलता है। देसी गायों का गोबर पोषक तत्वों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 से 500 करोड़ लाभकारी जीवाणु पाए जाते हैं वहीं दूसरी ओर 1 ग्राम विदेशी गायों के गोबर में केवल 7 करोड़ लाभकारी जीवाणु पाए जाते हैं।

प्रमुख कारक

बीजामृत: इसे गाय के गोबर और मूत्र आधारित योगों के साथ बीज उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है जो जड़ों से फैलने वाली बीमारियों से होने वाली बीमारियों से

पौधों को बचाते हैं।

जीवामृत: इसे जीवाणुओं से योकथाम के लिए उपयोग में लाया जाता है। जीवामृत की वजह से जमीन को पोषक तत्व मिलते हैं जो एक उत्प्रेरक का काम करते हैं और मिल्ली में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों की गतिविधि को भी बढ़ा देते हैं। इसका छिकाव सिंचाई के पानी के साथ, सीधा भूमि के ऊपर दो पौधों के बीच में और खड़ी फसल में किया जाता है। इसका उपयोग करने से फसलों की पैदावार में

सचिन कुमार

डॉ. सौरभ सोनी

भी बढ़ोतारी होती है।

मल्टिंग : मल्टिंग का उपयोग मिल्ली की नमी का संरक्षण तथा उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मिल्ली की सह घर पर तीन तरह से मल्टिंग की जाती है।

साइल मल्च : इसमें खेती के दौरान मिल्ली की ऊपरी सतह में मल्च का प्रयोग किया जाता है जो आस-पास की मिल्ली को इकट्ठा करके किया जाता है। इस तरह से मिल्ली की प्रतिधारण क्षमता को भी बढ़ाया जाता है।

स्ट्रॉमल्च : इस तरह की विशेष मल्टिंग में भूसे का उपयोग सब्जी उत्पादन में किया जाता है। इसमें चावल या गेहूं के भूसे का उपयोग किया जा सकता है जो मिल्ली की गुणवत्ता को भी बढ़ाने में कागड़ सिद्ध होते हैं।

लाइव मल्च : इस प्रक्रिया में एक खेत में एक साथ कई तरह की फसलें लगाई जाती हैं जो एक दूसरे को बढ़ावा देती है।

में मदद करती हैं। पालेकर के अनुसार मोनोकोट और डाइकोट एक साथ एक ही खेत में लगाई जाती हैं ताकि मिल्ली और फसलों को सभी आवश्यक तत्वों की अनुपूर्ति हो सके। इस तरह की खेती में फलीदार फसलों को चावल और गेहूं के साथ लगाते हैं। फलीदार फसलों नाइट्रोजन निर्धारण में मदद करती हैं जबकि चावल और गेहूं पोतश, फॉस्फेट और सल्फर जैसे अन्य तत्वों की अनुपूर्ति करते हैं।

वहशा (मिट्टी में नमी) : पौधों को बढ़ाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। पौधे धापासायानि वाष्प की मदद से भी बढ़ सकते हैं।

प्राकृतिक खेती के अधिन फायदे

जीरो बजट प्राकृतिक खेती में गहन कृषि और जैविक खेती के मुकाबले केवल 10 प्रतिशत पानी और 10 प्रतिशत बिजली की जरूरत होती है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती में कम लागत लगती है क्योंकि इसमें किसान किसी भी तरह के स्थानों का उपयोग नहीं करते हैं तथा किसान केवल अपने द्वारा बनाई गयी चीजों का उपयोग करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लागत की अपेक्षा ज्यादा मुनाफा होता है। जीरो बजट प्राकृतिक खेती से मिल्ली तथा मिल्ली की सह घर पर तीन तरह के मल्टिंग की जाती है।

साइल मल्च : इसमें खेती के दौरान मिल्ली की ऊपरी सतह में मल्च का प्रयोग किया जाता है जो आस-पास की मिल्ली को इकट्ठा करके किया जाता है। इस तरह से मिल्ली की प्रतिधारण क्षमता को भी बढ़ाया जाता है।

स्ट्रॉमल्च : इस तरह की विशेष मल्टिंग में भूसे का उपयोग सब्जी उत्पादन में किया जाता है। इसमें चावल या गेहूं के भूसे का उपयोग किया जा सकता है जो मिल्ली की गुणवत्ता को भी बढ़ाने में कागड़ सिद्ध होते हैं।

लाइव मल्च : इस प्रक्रिया में एक खेत में एक साथ कई तरह की फसलें लगाई जाती हैं जो एक दूसरे को बढ़ावा देती है।

जीरो बजट प्राकृतिक खेती से मिल्ली तथा मिल्ली की सह घर पर तीन तरह के मल्टिंग की जाती है।

खाद्य उपयोग

उमरे के फल और कोमल पत्तियां खाने में प्रयोग की जाती हैं। कच्चे फलों को उबाल कर स्वादिष्ट सब्जी, कचौरी, परांठा तथा आचार बनाने में प्रयोग किया जाता है। पके हुए फलों को सूजा कर पाउडर तैयार किया जाता है तथा इसका उपयोग आटे के रूप में या दूसरे आटे के साथ मिश्रित करके किया जा सकता है। यह पाउडर चीनी और दूध के साथ टॉनिक की भाँति भी लिया जा सकता है। पके हुए फल भी खाने में प्रयोग होते हैं। उमरे के फल अप्रैल से अगस्त तक एकत्रित किए जा सकते हैं।

फल कुछ, त्वचा की उपयोग

उमरे के फल और कोमल पत्तियां खाने में प्रयोग की जाती हैं। कच्चे फलों को सूजा कर पाउडर तैयार किया जाता है तथा इसका उपयोग श्वास संबंधित रोगों, आंत रोगों, घाव भरों, बवासीर और त्वचा संक्रमण के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इस पौधे के लेटेक्स को दर्द और सूजन को कम करने के लिए घावों पर बाहरी रूप से लगाया जाता है। चीनी के साथ इसका उपयोग बच्चों में दस्त और पैचिश को कम करने और पुरुषों में यौन शक्ति में

मधुमक्खियों का कीटनाशक रसायनों से बचाव

मधुमक्खियां अपने स्वभाव के अनुसार फूलों से पराग व रस अपने मौन गृह में लाती हैं जोकि इनके तथा इनके शिशुओं के लिए आवश्यक होते हैं। मधुमक्खियां जहरीले पराग को भी छोड़ती हैं, ऐसी अवस्था में पराग की फ्रेमों को निकाल कर पानी में डुबो देते हैं तथा जहरीले पराग को निकाल देते हैं।

मौनवंशों में विषप्रभाव के लक्षण

मधुमक्खियां जहरीले कीटनाशकों के सम्पर्क में आने के पश्चात बहुत संख्या में मौनगृहों के बाहर मरी हुई देखी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रासों में ही दम तोड़ देती हैं। कुछ प्रभावित

फ्रेमों को दूर-दूर कर देते हैं ताकि हवा सही मात्रा में मिल सके। पानी का प्रबंध भी बक्सों के अन्दर कर देना चाहिए। मधुमक्खियों जहरीले कीटनाशकों के लक्षण में खुराक देनी चाहिए ताकि उन्हें बचाया जा सके।

जहां तक हो कीटों से फसलों को बचाने के लिए गैर रसायनिक तरीके

ही अपाएं। रसायनों का प्रयोग अन्य विकल्प न रहने की स्थिति में ही करें।

अगर रसायनों का इस्तेमाल

मौन गृह में लाती है तो कीट छिकाव

तथा छिकाव के लिए लाती है।

मौन गृह में लाती है तो कीट छिकाव

तथा छिकाव के लिए लाती है।

मौन गृह में लाती है तो कीट छिकाव

तथा छिकाव के लिए लाती है।

मौन गृह में लाती है तो कीट छिकाव

तथा छिकाव के लिए लाती है।

मौन गृह में लाती है तो कीट छिकाव

तथा छिकाव के लिए लाती है।

मौन गृह में लाती है तो कीट छिकाव

तथा छिकाव के लिए लाती है।

मौन गृह में लाती है तो कीट छिकाव

तथा छिकाव के लिए लाती है।

मौन गृह में



अनुपम है आउटर सिराज के धनाह का ठिरशू मेला

यह मेला 7 बैसाख की संध्या को स्थानीय देवता रखाऊ नाग जी की रथ यात्रा से शुरू होता है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के बीच नाग देवता की रथयात्रा गांव के साथ लगते हैं। देवस्थान (देव थाणी) तक निकाली जाती है।

हिमाचल का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क पठल पर जो छोटी उभर कर सबसे पहले आती है, वह है बर्फ से लकड़क पहाड़ की चोटियाँ और घने जंगल। लेकिन हिमाचल की असल छवि कहीं ज्यादा व्यापक एवं खूबसूरत है। सुंदरता यहां के पहाड़ों पर बसे छोटे-छोटे गांवों एवं यहां की संस्कृति में बसती है। हिमाचल के गांवों में अनेक रीति-रिवाजों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रचलन है। आज भी यहां के लोगों ने इन पौराणिक परंपराओं एवं रिवाजों को जीवित रखा है। हां, हिमाचल की बहुमूल्य संस्कृति आज भी यहां के गांवों में मनाए जाने वाले मेलों एवं उत्सवों में साफ देखी जा सकती है।

ऐसी ही परंपरा को जीवित रखा है जिला कुल्लू के आउटर सिराज के दूरदराज स्थित निवारण फाटी के छोटे से गांव धनाह ने। यहां हर वर्ष 8 बैसाख के दिन 'ठिरशू' नामक पारंपरिक मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला 7 बैसाख की संध्या को स्थानीय देवता रखाऊ नाग जी की रथ यात्रा से शुरू होता है।

पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के बीच नाग देवता की रथयात्रा गांव के साथ लगते देवस्थान (देव थाणी) तक निकाली जाती है। वहां पहुंचकर नाग देवता अपने विशित स्थान पर बैठते हैं नाग देवता की पूजा अर्चना के साथ मां काली का आवाहन किया जाता है। इसके पश्चात् ग्रामीणों द्वारा सुंदर पहाड़ी नाटी के साथ नाग देवता के रथ को वापस मंदिर परिसर में लाया जाता है। अगले दिन यानी 8 बैसाख को नाग देवता अपने रथ पर सवार होकर गांव के बीचोबीच स्थित प्रांगण में पूरे विधि विधान के

रूप राज शर्मा

परंपरा यानी 'स्वांग' का प्रदर्शन किया जाता है। महाभारत एवं मुगल काल की घटनाओं एवं सामाजिक जीवन से प्रेरित है स्वांग

ग्रामीणों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वांग जैसे मेंढक वृत्त, मुगल मञ्चण, ढोल बैटी, ब्रह्मारी, साहूकार आदि के माध्यम से महाभारत तथा मुगल काल में घटित घटनाओं को जीवत किया जाता है। 500 से भी अधिक वर्ष पूर्व से इस

मेले में स्वांगों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। प्रत्येक स्वांग अपने

आप में अतीत के रहस्यों एवं संदेश को समाए हुए लोगों का मनोरंजन तो करते ही हैं साथ ही सैकड़ों वर्ष पूर्व के मानव जीवन एवं सामाजिक परिवेश की झलक भी दिखाते हैं। स्वांगों द्वारा पहने गए परिधान एवं मुखौटे आकर्षण का मुख्य केंद्र रहते हैं।

स्वांग के साथ-साथ तलवारबाजी भी है मेले का मुख्य आकर्षण

मेले में स्वांगों के साथ-साथ तलवारबाजी की कला का भी प्रदर्शन किया जाता है। स्थानीय ग्रामीण श्री चांद कुमार शर्मा एवं श्री देशराज शर्मा का कहना है कि उन्हें यह तलवारबाजी की कला अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है।

प्राचीन समय में गांव के लोगों द्वारा इस कौशल का प्रयोग बाहरी अक्रांताओं से गांव की रक्षा एवं देवता के खजाने की सुरक्षा के लिए किया जाता था। इसी परंपरा को स्थानीय ग्रामीणों ने आज भी जिंदा रखा है। धनाह गांव के लोग तलवारबाजी, कला में आज भी पारंगत



क्या कोई जानता है कि पश्चिमी हिमालय का हरिद्वार लाहुल-स्पीति का चंद्रभागा संगम है। युगों-युगों से चंद्रभागा संगम जहां इतिहास का साक्षी रहा है, वहीं, पश्चिमी हिमालय के लोग इस संगम को हरिद्वार के समान ही पवित्र मानते हैं। कबायली जिला सहित लेह-लद्दाख तथा चीन अधिकृत तिब्बत के लोगों के लिए यह स्थल हरिद्वार से कम नहीं है। आज भी लोग इसी संगम स्थल पर अपने पूर्वजों की अस्थियां बहाकर पुण्य करते हैं। सर्दियों में कबायली लोग यह माह तक बर्फ के कारावास में कैद हो जाते थे और इसी स्थल में अस्थियां प्रवाहित करते रहे हैं। हालांकि अब अटल सुरुंग रोहतांग के खुल जाने से कबायली क्षेत्र के लोगों का आवागमन आसान हो गया है लेकिन अब यह स्थल धार्मिक पर्यटक नगरी के रूप में उभर कर सामने आ गया है। हालांकि यहां का धार्मिक महत्व पहले से ही है लेकिन रोहतांग दर्ये के बंद होने और अति दुर्गम होने के कारण इस स्थल के दर्शन सीमित लोग ही कर पाते थे।

अब अटल सुरुंग के खुल जाने से देश-दुनिया के लोगों के लिए यह सुंदर स्थल आकर्षण का केंद्र बन चुका है। अब इस पवित्र स्थल के संरक्षण की भी भी तैयारियां होने लगी हैं। लाहुल-स्पीति के इस संगम स्थल के इतिहास पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो भागा-चंद्रा ने कई युग देखे हैं। बौद्ध मन्त्रालय के प्रसिद्ध ग्रन्थ विमान बत्थू में इस नदी को तंगती कहा गया है। अरबी और फारसी में मुगलों ने इस नदी का नाम 'चिनाब' दिया जिसका अर्थ था 'आव ए-चीन' यानी कि स्वर्ग का पानी। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ विमान बत्थू में इस नदी को तंगती कहा गया है। अरबी और फारसी में मुगलों ने इस नदी का नाम 'चिनाब' दिया जिसका अर्थ था 'आव ए-चीन' यानी कि चीन से आने वाला पानी। वहीं, युनानी ग्रन्थों में नदी का नाम हाईपरिस पड़ा। युनानियों ने इस नदी को अपशुगुनी नदी माना, क्योंकि सिकंदर की छती में अधिरी तीर इसी नदी के तट पर लगा था। माना जाता है कि सिकंदर को यहीं आकर शिक्षस्त मिली थी। वहीं, वैदिक काल में चंद्रभागा नदी का नाम 'अस्तिकी' पड़ा। ऋषेद के नदी सोखत अध्याय में नदी को अस्तिकी



नाम से पुकारा गया है। पौराणिक काल में शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में इस नदी को चंद्रभागा का नाम दिया है। वहीं, बौद्ध सिद्धघंटापा ग्रन्थ में विस्तार से बताया गया है कि इसी संगम पर द्रोपदी का अंतिम संस्कार हुआ था। यहीं नहीं इस ग्रन्थ में यह भी दर्शाया गया है कि यह स्थल लोमश ऋषि की तपोस्थली है। वर्तमान में इस नदी को लाहुल-स्पीति में चंद्रभागा व वहां से आगे चिनाब के नाम से जाना जाता है। यास बात यह है कि यह नदी पश्चिमी हिमालय के कई देशों को सीधी है जिसमें तिब्बत, भारत व पाकिस्तान भी शामिल हैं। गोर रहे कि वर्तमान में लाहुल-स्पीति का चंद्रा नदी से आने वाले ग्रन्थों ने इसी संगम स्थल पर अस्थियां विसर्जित करते आए हैं। इसलिए उनके लिए यह स्थल पवित्र तीर्थ हरिद्वार से कम नहीं है और इस स्थल का वर्तमान में

धनेश गौतम

है। लाहुल-स्पीति के लोगों का कहना है कि वे भौगोलिक तौर पर अति दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं जो छ माह तक बर्फ के कारावास में परिवर्तित हो जाता है। उसी स्थिति को नजर में रखते हुए इस क्षेत्र के लोग सदियों से इसी संगम स्थल पर अस्थियां विसर्जित करते आए हैं। इसलिए उनके लिए यह स्थल पवित्र तीर्थ हरिद्वार से कम नहीं है और इस स्थल का वर्तमान में

गिरती है। चंद्रा नदी स्पीति धारी की तरफ से आती है और भागा-चंद्रा दोनों नदियों का उदगम स्थल बागलाचा दर्ता है जबकि भागा नदी लाहुल धारी से आती है। खास बात यह है कि बागलाचा दर्ता के एक तरफ से चंद्रा नदी निकलती है जबकि दूसरे छोर से भागा निकलती है। चंद्रा नदी स्पीति धारी को सिंचित करती है और भागा लाहुल धारी को। रोहतांग टनल में आरामदायक सफर किया जा सकता है। दूसरी तरफ निकलने पर शीत मरुस्थल की सुंदर वादियों के दर्शन हो जाते हैं। टनल के पार कुछ ही दूरी में लाहुल का पहला गांव सिस्सू नजर आएगा और यहां घेपन ऋषि का प्राचीन मंदिर है। घेपन ऋषि के दर्शन के बाद सीधे उसी मार्ग दिल्ली-लेह मार्ग पर आगे बढ़ते रहे गोदला गांव व और अन्य छोटे गांव आते हैं और गोदला से आगे तांदी पड़ता है। अटल रोहतांग टनल से तांदी तक का यह सफर 3.6.8 किलोमीटर का है और बस यहां पर भागा-चंद्रा नदी का संगम स्थल है। जहां आप लोगों को इस पवित्र स्थल के दर्शन हो जाएंगे। इस संगम से जिला मुख्यालय केलांग की दूरी 9.5 किलोमीटर है। सर्दियों में चंद्रभागा नदी पूरी तरह से बर्फ में जम जाती है और अकई बार तो संगम का पानी इतना ठोस हो जाता है कि स्थानीय लोग इस पर आइसकेटिंग तक कर डालते हैं। उस समय यह स्वर्गिक अनुभूति करवाता है। गर्मियों में स्थल के चारों तरफ सुंदर

है। सभी स्वांग कलाओं के प्रदर्शन के उपरांत मैदान के बीच में लगाए गए देवदार के पेड़ (जिसे स्थानीय भाषा में 'पड़ेई' कहा जाता है) के बीच एक खेल का आयोजन किया जाता है, जिसमें पेड़ की चोटी पर बंधे देव वस्त्र (स्थानीय भाषा में शाड़ी) को निकालने के लिए गांव के नौजवानों एवं अन्य लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है। जो भी व्यक्ति वस्त्र को पेड़ पर चढ़कर निकालने में सफल रहता है उसे नाटी में सबसे आगे नाचने का मौका मिलता है। मनमोहक कुल्लुवी नाटी एवं मधुर धुनों के बीच नाग देवता के रथ को उनकी कोठी में वापिस पहुंचाया जाता है। इसके पश्चात् सभी ग्रामीण सुबह तक अपने इष्ट देवता रखाऊ नाग एवं मां दुर्गा धनेश्वरी की लोकगीत एवं पारंपरिक भजनों से स्तुति करते हैं। रात्रि स्वांग एवं नाटी के प्रदर्शन के बीच सुबह की पहली किरण निकलते ही इस ऐतिहासिक एवं पौराणिक मेले का विधि-विधान के साथ समाप्त होता है। इस प्रकार यह मेला निश्चित रूप से हिमाचल की बहुमूल्य संस्कृति का परिचायक है, जिसे धनाह वासियों न

हास्य व्यंग्य

ब्रेकफास्ट बनाम उपहार

बलिहारी है पश्चिमी जीवन शैली की कि पश्चिम के लोग सुबह से शाम तक कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। पशु-पक्षियों की तरह स्वच्छन्द-निश्चिन्त जीवन जीते हैं, जीने के लिए नहीं, खाने के लिए जीते हैं, डटकर काम करते हैं और जीभर कर खाते हैं। वर्तमान में जीते हैं भविष्य की चिक्का करके वर्तमान का मजा किरकिरा नहीं करते। मेरे प्रिय शिष्य हैं- नरेन्द्र नाथ 'चट्टान'। उनका कहना है कि हम भारतीय जिस पतल में खाते थे, उसी में छेद करने लगे, इसलिये आज प्रीति भोज (बैकॉस्टर्स) का सूखपात हुआ है। प्रीति भोज पर उनकी हास्य फुहार देखिये:-

हम प्रीति भोज में जाते हैं और ऐसी प्रीति निभाते हैं।

न्याय रुपये थमाते हैं और न्याय को ले जाते हैं।।।

हम खाते हैं पर जीने के लिये खाते हैं।।।

गर फोट का भिल जाये तो मरते तक खाते हैं।।।

हम जो ब्रात, उपवास आदि करते हैं ऐसे पाखण्डों से वे दूर रहते हैं, ठीक हमारे पूर्वज महर्षि चार्वाक की तरह-यावजीवेत् सुखं जीवेदर्शं कृत्वा धृतां पिवेत् ! 'फास्ट' का अर्थ- अनशन या भोजन करना है। शयनावधि (सोते रहने का कूल समय) ही उनके शब्दों में 'फास्ट' है जो बिना कुछ खाए-पिए सोने में बदल हो गई- वर्ष्य चली गई। सुबह जागकर जब वे चाय के साथ कुछ खाते हैं यही उनके 'फास्ट' का ब्रेक है, ब्रेकफास्ट है, जिसे हम उपवास का 'पारा' कहते हैं।

कुछ लोग इसे 'जलपान' कहने लगे हैं पता नहीं, किस विद्वान ने इसे यह नाम दे दिया ? जबकि 'जलपान' का शाब्दिक अर्थ- 'पानी पीना' ही होगा, योद्धा खाना या स्वत्पाहार नहीं।

एक दिन हमारे एक साथी प्रोफेसर की स्थानीय पेपर में रचना छपी। किसी साथी प्रोफेसर ने उन्हें बधाई दी। स्वामी मिथ्यानंद ने सुन लिया। फौरन आ गए, रचना तो उन्होंने पढ़ी नहीं थी, न कभी पढ़ने वाले थे पर बधाई देने में बाप का क्या जाता है? बधाई देते हुए बोले- प्रोफेसर साहब, क्या लिखा है, क्या शैली है हिन्दी में गोस्वामी तुलसीदास के बाद यदि कोई कवि पैदा हुआ है तो आप हैं। जिसकी कविता के मर्म को प्राचार्य के.पी. तिवारी से लेकर हीरालाल तक समझ सकता है।

फिर भी अथविदिश से प्रचलित 'जलपान' और 'स्वत्पाहार' को स्वीकार कर भी ले तो इससे 'सुबह के नाश्ते' का नहीं, किसी भी समय के नाश्ते का अर्थ निकलता है। यानी जलपान, स्वत्पाहार या नाश्ता किसी भी समय, कभी भी और कहीं भी लिया जा सकता है।

वै से इस सिलसिले में मुझे 1967-1968 का एक वाक्या याद आ गया जब मध्यप्रदेश में 'अंग्रेजी हटाओ, राष्ट्रभाषा लाओ' का अभियान यूनिवर्सिटी और कालेजों के छात्रों ने जोर-शोर से चलाया था, रातों-रात दुकानों, होटलों, कार्यालयों के नाम पट्ट अंग्रेजी से बदलकर हिन्दी में कर दिए गए थे। उसी अवधि में भोपाल गया था, नाश्ता करने के लिए मैं जिस 'होटल' में घुस रहा था, उसका नाम पट्ट पढ़कर मैं चौक गया लिया था- 'उपहार गृह' आस-पास की अन्य होटलों के नाम पट्टों पर भी दृष्टि डाली

पेट में जाते ही खात्म हो जाता है।

दूसरों को उलू बनाकर या मुर्गा फांसकर किए जाने वाले नाश्ते का स्वाद चिरस्थायी नहीं उत्तरोत्तर मजा देने वाला होता है। मुफ्त नाश्ताओं जब चट्टाने ले-लेकर अपने मुफ्त में दूसरों से नाश्ता कर लेने की विजयगाथा के साथ उसका वर्णन यहां-वहां करते

फिरते हैं तब उसका

स्वाद क्षण-क्षण में नवीनता पा-पाकर लजीज से- मो स्ट लजीज बनता रहता है।

हमारे एक साथी हैं- स्वामी मिथ्यानंद। सदै व मिथ्या ही बोलने वाले, मिथ्या के अलावा कुछ न बोलने और मिथ्या

बोलकर आनंदित होने, दूसरों को होनाने और चिन्दने वाले भी। वे धोरहर हैं, मैं 30 साल पहले जब इस महाविद्यालय में आया था तबसे उनके शरीर में पेट के स्थान पर स्थायी रूप से 30-35 लीटर कैपेसिटी के धड़े को विपक्ष दुआ दे रहा हूं जो अब मुफ्त का आ-आकर बद्ध-बद्ध पचास लीटर की कैपेसिटी वाला हो गया है।

एक दिन हमारे एक साथी प्रोफेसर की स्थानीय पेपर में रचना छपी। किसी साथी प्रोफेसर ने उन्हें बधाई दी। स्वामी मिथ्यानंद ने सुन लिया। फौरन आ गए, रचना तो उन्होंने पढ़ी नहीं थी, न कभी पढ़ने वाले थे पर बधाई देने में बाप का क्या जाता है? बधाई देते हुए बोले- प्रोफेसर साहब, क्या लिखा है, क्या शैली है हिन्दी में गोस्वामी तुलसीदास के नाश्ता करना और पेमेन्ट करना अथवा दूसरों के ऑफर पर उनके साथ उन्हीं के पैसों में नाश्ता करना। तीसरा दूसरे के घर में नाश्ता करना और उससे नाश्ता करने के बदले में उसे उपहास का पात्र बनाना। अन्य प्रकार के नाश्तों का स्वाद और मजा तो उसके

कविता

पिता का थैला

एक भी दिन नहीं देखा उन्हें थैले के बिना घर से बाहर जाते, ज्यादा बोझ से जब तभी टूट जाती

देखा था अक्सर उन्हें मां से उसे सिलवाते॥

हम क्या पढ़ते-लिखते हैं, वो समझ नहीं पाते थे, नम्बर जितने भी आते, पर पास होने पर वो थैले में मिठाई जरूर लाते थे।

वो हमारे लिए जितना भी कर लें कभी भी नहीं जाता थे, वो अपने थैले में सारी दुनिया के सुख भर लाते थे।

॥ अतुल कुमार

सामान्य ज्ञान

जल शक्ति अभियान : कैच द रेन?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 मार्च, 2021 को बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व जल दिवस के मौके पर 'जल शक्ति अभियान : कैच द रेन' का शुभारम्भ किया। यह नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय स्तर की अपनी तरह की पहली परियोजना है। यह अभियान देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ 'कैच द रेन : जहां भी, जब भी संभव हो वर्षा के जल का संग्रह करें' थीम के साथ शुरू किया गया। इस अभियान को देश में मानसून पूर्व और मानसून अवधि के दोरान 22 मार्च, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य राज्य और सभी हितधारकों को वर्षा के जल का संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी की स्थितियों के अनुकूल रेन वाटर हार्डिंग्स स्ट्रक्चर्स का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है।

- 1 हाल ही में काला नमक चावल महोत्सव कहां आयोजित किया गया ?
- 2 मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है ?
- 3 वर्ष 2019 व 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया ?
- 4 भारत के प्रथम मुख्य व्यायाधीश कौन थे ?
- 5 वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है ?
- 6 संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को मोटे अनाजों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है ?
- 7 'हाऊ दू एवॉड ए क्लाइमेट डिजास्टर' के लेखक कौन हैं ?
- 8 जी-7 राष्ट्रों की 47वीं समिट जून 2021 में कहां प्रस्तावित है ?
- 9 एटीपी रैंकिंग में सर्वाधिक समय तक नम्बर एक

10. खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी ने बनाया ?
11. हिमाचल प्रदेश अटल चिकित्सा अनुसंधान विश्वविद्यालय नेचॉकैप के कुलपति कौन हैं ?
12. स्टिटजरलैंड के किस राजदूत ने एक साइन बोर्ड स्थापित कर खाजियार को आधिकारिक तौर पर मिनी स्टिटजरलैंड का नाम दिया ?
13. डांगी और डेपक किस जिले का मशहूर लोकनृत्य है ?
14. गांधी हत्या का मुकदमा शिमला के किस सुविधात भवन में चला था ?
15. हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें सङ्क युविधा से जुड़ी हैं ?

प्रस्तुति : मोहित शर्मा

उत्तर- 1. उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में, 2. भारत व बंगला देश (27 मार्च, 2021 को शुरू की गई), 3. बंगलुरु शेख मुजीब उर रहमान (वर्ष 2020), ओमान के दिवंगत सुलतान काकूस बिद सैद अल सैद, 4. हरिलाल जे. कानिया (26 जनवरी, 1950 से 06 नवम्बर, 1951), 5. प्रो. शरद पगारे को (वर्ष 2010 में प्रकाशित उनके ऐतिहासिक उपव्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए), 6. वर्ष 2023, 7. बिल गेट्स, 8. ब्रिटेन, 9. नोवाक जोकोविच, 10. डॉ. सुरेंद्र कश्यप, 11. डब्ल्यू. प्लेजर, 12. हमीरपुर, 13. जिला चंबा के छत्तराड़ी इलाके का, 14. पिटरहॉफ, 15. 3162 पंचायतें (10,488 गांव)

रास्ते में जो भी मिलता गया-प्रोफेसर, प्रयोगशाला शिक्षक, भूत्य सभी से उके साहब की रचना की तारीफ करते हुए सभी को साथ लेकर होटल पहुंचे। 30-35 लोग हो गए।

जो कुछ होटल में था, सभी हम मुफ्तखोरों ने चट कर लिया, चाय पी,

पान खाया, स्वामीजी ने बम भोले का प्रसाद- एक पैकिट सिगरेट ली और

उके को दो-ढाई सौ का चूना लगाकर महाविद्यालय चले गए। अब तो जब भी उन्हें पता चलता उके साहब की रचना आई है, उनका चाय-नाश्ता पक जाता।

एक दिन उन्होंने रचना छपने की बधाई दी तो उके साहब बोले- 'सर आज तो मेरी कोई रचना नहीं आई है

व्यंजन

स्वाद और पोषण का खजाना गेहूं के उत्पाद

भारत में मक्की के बाद गेहूं ही एक ऐसी फसल है जिसे पूरे भारत में उगाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं का आटा मैदा की अपेक्षा ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। गेहूं पेट के लिए बहुत हल्की व सुप्राच्य होती है।

गेहूं के विभिन्न व्यंजन व खाद्य उत्पाद- गेहूं से आटा बनाने के अलावा भी इसका उपयोग बहुत से खाद्य उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है।

सीरा

सामग्री : गेहूं = 1 कि.ग्रा., धी = 80 ग्राम, चीनी = 50 ग्राम, पानी = 150 मि.ली.

विधि : गेहूं को दो से चार दिन पानी में अंधेरे कर रखें। चार दिन बाद उपरी सतह का पानी फेंक दें व बाकि गेहूं को निकाल कर ग्राइंडर में पीस लें। फिर पानी से अंधेरे से थोकर गहन को निकालकर धूप में छोटे-छोटे गोले बना लें व सुखा लें। सुखाने के बाद इस सिरे को पकाने के लिए 100 ग्राम सीरा लेकर इसमें पानी व चीनी मिला कर पेस्ट बनाएं। धी को गर्म करके इस पेस्ट को उसमें तब तक पकाएं जब तक की कड़ाही के सिरे से न चिपके।

गुजिया - गेहूं का आटा = 2/3 कप, दही = 1/2 चम्मच, धी = 1 चम्मच पानी गूंथने के लिए।

अरने के लिये - नारियल 2 कप, चोया 1/2 कप, किशमिश 1/4 कप, पीसी हुई चीनी 1/2 कप, पीसी हुई छोटी इलाइची, धी तलने के लिए, बादाम काजू 1/2 कप पिसे हुए।

विधि - अरने वाले मिश्रण को अंधेरे से मिला ले जो पिसने वाली वस्तुएं हैं उनका पाउडर बना लें। आठे में दही, धी डालकर अंधेरे से गूंथ लें फिर गोल रोटी बना कर उसमें मिश्रण भरकर गुजिया का आकार बना कर बंद कर लें व हल्का भूंग होने तक तल लें।

भूरे

सामग्री - गेहूं का आटा = 100 ग्राम, खमीर = 5 ग्राम, तेल तलने के लिए, आटा गूंथने के लिए पानी

विधि : आठे में खमीर डालकर पानी मिलाकर अंधेरे से आटा गूंथ लें व कपड़े से ढक कर डेढ़ घंटे के लिए रख लें जब अमीरीकरण हो जाये तो तेल गर्म करके उसमें भूरे प्राई कर लें।

कचौरी : यदि कचौरी बनानी हो तो विधि अनुसार आटा गूंथ लें व अलग से किसी भी दाल जैसे सोयाबीन, माश, अराहोट/माह की दाल/सोया दाल = 200 ग्राम, चीनी = 10 ग्राम, खसखास/अराहोट = 2.5 ग्राम, हल्दी = 2 ग्राम, धी = 10 ग्राम, खसखास/अराहोट = 2.5 ग्राम, माह की दाल/सोया दाल = 200 ग्राम, लहसुन = 12 कलियां, गरम मसाला = 10 ग्राम, मिर्च पाउडर 10 ग्राम, नमक = 10 ग्राम।

विधि : आठे में अमीर डालकर पानी मिलाकर अंधेरे से आटा गूंथ लें व कपड़े से ढक कर डेढ़ घंटे के लिए रख लें जब अमीरीकरण हो जाये तो तेल गर्म करके उसमें भूरे प्राई कर लें। उस पर अमीरीकरण के लिए रखें। जब यह आटा दोगुना हो जाये तो आठे गुनगुने पानी से गूंथ लें। अब इस आठे को

लघुकथा

पानी की कमाई

वह दूध बेचने का धन्या करने लगी थी। पहले-पहल तो वह दूध दोहते ही, दूध लेने आए ग्राहकों को बिना मिलावट के दूध दे डालती थी। पानी की एक भी कूट वह दूध में नहीं मिलाती थी। लेकिन अब वह मंहगाई का रोना रोती। घर के खर्चों की बातें करने लगती। उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। पढ़ने जाते हैं स्कूल। ट्यूशन भी पढ़ते हैं। उनका भी खूब खर्च होता है।

अब जबकि उसके पास गार्यों की संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन ग्राहकों की अधिक संख्या होने पर, वह बेहद लालची हो गई है। अब वह दूध में उतना पानी अवश्य मिलाती है जितना उसमें खप जाए। उसकी मासिक आमदनी भी बढ़ गई थी। वह मन ही मन खुश थी। उसके कई अपने खर्चे भी इसी से निकल जाते। पर्ति के सामने उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था।

लेकिन उसके बेटे जो पास वाली दुकान पर बार-बार मां से रुपये लेकर सामान लेते थे उनकी आदतें बिगड़ने लगी थीं। वह मां के साथ छूट बोलकर भी रुपये ढाने लगे थे। कभी कहते प्रोजेक्टर्स के बारे में बिक्री करते थे। फास्टफूड के वह इतने दीवाने थे कि घर से सुबह लंच लेकर नहीं जाते। मां भी उन्हें मांगने पर झटक लगते थे, पर इतना अवश्य कहती, खूब मन लगाकर पढ़ना। मेरी तरह घास नहीं काटना। मैं तो छहरी अनपढ़। बच्चे आए दिन मां से रुपये लेते रहते। चटकारे ले-लेकर बाजार की चीजें खाते। स्कूल से भी बंक मारने लगे थे। मां यह नहीं जानती थी, जो उसने पानी डालकर दूध बेचा है तथा रुपये कमाए हैं, वह सारी कमाई पानी में ही जा रही है।

■ नरेश कुमार 'उदास'

दाल चना इत्यादि का मिश्रण भिगोकर छिलके निकाल कर पीस कर मसाले व नमक मिला कर तैयार कर लें व गोल-गोल पेंडे बना कर उसमें मिश्रण को अच्छे से भरें व रोटियां बनाकर तल लें। इसे पूदीने व इमली की चटनी के साथ परोसें।

पिण्डी : सामग्री गेहूं का आटा = 150 ग्राम, मूंगफली पीसी हुई = 50 ग्राम, सोया आटा = 75 ग्राम, चीनी = 200 ग्राम, बेसन = 75 ग्राम, धी = 100 ग्राम, चौलाई दाना भूंग हुआ पाउडर = 25 ग्राम

विधि-आठे को मिलाकर छानकर भूंग लें। इसके अलावा मूंगफली का पाउडर व चौलाई दाना को भूंग कर आठे में मिला लें। 5 से 10 मिनट तक हिलाते हुए पकाएं व गोल गोल पिण्डियां बना लें।

पंजीयी

सामग्री : गेहूं का आटा = 100 ग्राम, किशमिश = 15 ग्राम, सौंफ = 5 ग्राम, सोया आटा = 50 ग्राम, बादाम = 15 ग्राम, चीनी = 100 ग्राम, मूंग दाल आटा = 50 ग्राम, काजू = 15 ग्राम, धी = 40 मि.ली., नारियल बुरा = 50 ग्राम, छोटी इलाइची = 5

विधि : तीनों आठे को अलग भूंग लें। उस पर चीनी, व अन्य भूंग हुए काजू बादाम व अन्य सामग्री भी अच्छे से मिला लें। इस पर नारियल बुरा डालते हुए पकाएं। जब यह आठे बन जाएं तो उसमें काजू, बूंग अंधेरे से छाने लें।

सीद्धा

सामग्री - गेहूं का आटा = 1/2 किलो., खमीर = 2.5 ग्राम, हल्दी = 2 ग्राम, चीनी = 10 ग्राम, खसखास/अराहोट/माह की दाल/सोया दाल = 200 ग्राम, लहसुन = 12 कलियां, गरम मसाला = 10 ग्राम, नमक = 10 ग्राम, मिर्च पाउडर 10 ग्राम, व धनिया = 1 ग्राम, मसाला = 1 चम्मच, धनिया = 1 चम्मच, तलने के लिए तेल।

विधि : आठे को अलग भूंग लें। उस पर चीनी, व अन्य भूंग हुए काजू बादाम व अन्य सामग्री भी अच्छे से मिला कर हिलाते हुए पकाएं। जब यह आठे बन जाएं तो उसमें काजू, बूंग अंधेरे से छाने लें।

जमीरीकरण के लिए 3-6 घंटे के लिए सूखी गीले कपड़ों से ढक कर रख लो। यदि आपने खसखास सिंडू भरने के लिए प्रयोग करना है तो उसे पहले 30 मिनट तक उबाल लें व ठंडा करके पानी निकाल कर मिक्सर में पीस कर पेस्ट बना लें। इसमें अदरक, लहसुन, प्याज

गाम, पानी = 350-400 मि.ली. **विधि :** आठे को छानके के बाद धीरे-धीरे पानी मिलाते हुए पतला पेस्ट बनाये। तबे पर तेल लगा कर कठोरी से मिश्रण की पतली तह में फैलाएं व दोनों तरफ से पका लें और आलू के साथ गर्म-गर्म परोसें।

गुलगुले

सामग्री - गेहूं का आटा = 200 ग्राम, चीनी = 70 ग्राम अराहोट, बादाम, काजू = 20 ग्राम, तेल तलने के लिए।

विधि : चीनी को पानी में धोलकर तब तक गर्म करें जब तक की चीनी न घुल जाये। इस धोल में आठे को डाल कर अंधेरे से फेंटे लें ताकि नर्म धोल बन जाये। इसमें इच्छानुसार अराहोट बादाम, काजू इत्यादि पीस कर मिला लें व 10 मिनट तक छोड़ दें। कद्दई में तेल गरम करके गुलगुले तल लें व भूंग होने पर निकाल लें।

ओटे का हलवा

सामग्री - आटा = 200 ग्राम, नमक = स्वादानुसार, आलू = 500 ग्राम, हरी मिर्च = 2 कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ = 2 बड़े चम्मच, जीरा = एक चम्मच, धनिया = एक चम्मच, गरम मसाला = 1 चम्मच, धनिया = 1 चम्मच, तलने के लिए तेल।

विधि : आठे को अंधेरे से छाने लें फिर कद्दई में धी गर्म करके आठे को अंधेरे से भूंग लें चीनी व पानी व मूंगफली का प्रयोग भी किया जा सकता है।

दलिया : नमकीन दलिया, धनियां व मीठा दलिया

दलिया = 50 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर = 5 ग्राम या इच्छानुसार, मूंग

कविता

नारी

जीवन क्या है ये,
मां के अहसानों की कहानी है।

कभी कौशल्या व्याकुल

कभी लव-कुश की जुबानी है।

अभिशापों को जो झेले
जीवन सुधा वो न्यारी है।

आंखों में लिए करुणा

जीवन का वरदान नारी है।

बहन बेटी नहीं युग में

मां का अवतार नारी है।



राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बचुर्मल कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर

कोरोना वैक्सीन की पहली व दूसरी खुराक के मध्य अंतर कम करने के लिए प्रभावशाली प्रणाली विकसित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने गत दिनों शिमला जिले में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि जिले में कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि होने की स्थिति में मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी न आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से जिले में आने वाले सभी लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। जैसे ही कोई व्यक्ति बाहरी राज्यों से प्रदेश में आता है, तो इसकी जानकारी सम्बन्धित क्षेत्रों के आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से भी साझा करे ताकि होम क्वारंटीन वियामों का प्रभावशाली तरीके से पालन करने की उपयोग की अनुमति से सम्बन्धित मामला उत्तया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी की नई

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना

ओपीडी में चरणबद्ध तरीके से 300 अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता का विर्माण किया जाएगा। आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला में 50 अतिरिक्त बिस्तरों, नागरिक अस्पताल जुन्डा में 50 अतिरिक्त बिस्तरों व दुटीकण्डी पार्किंग में 100 बिस्तरों की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध करवाई जाएगी। रोहदू, रामपुर खुंहोर के खंडों और टियोग नागरिक अस्पतालों में बिस्तरों को क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जाए चाहिए। उन्होंने कहा कि साधारण जनता को स्वेच्छा से टीकाकरण और कोविड-19 से बचाव के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए शिमला शहर या निकटवर्ती स्थान पर प्री फेब्रिकेटिड 200 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों से शिमला में सेना अस्पताल के उपयोग की अनुमति से सम्बन्धित मामला उत्तया जाएगा। होम आइसोलेशन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साधारण जनता को स्वेच्छा से टीकाकरण और कोविड-19 से बचाव के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला जिला में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जिले में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अस्पतालों में भीड़ को कम किया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से रोहदू और रामपुर के अस्पतालों के लिए नए गैस प्लांट स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। उपायुक्त अदित्य नेगी ने जानकारी दी कि जिले में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1648 है और रिकवरी दर 86.1 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल तक जिले में कोविड के 165029 संपूर्ण लिए गए। उन्होंने शिमला जिले में बेमौसमी बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान पर एक प्रस्तुति भी दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, महापौर सत्या कौंडल, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी इत्यादि ने वर्तुअल माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री की पुरस्कृत पंचायतों को बधाई

(पृष्ठ एक का शेष) विकासित कार्यों में दक्षता एवं गुणवत्ता लाने के लिए राज्य में आरंभ की गई ई-गवर्नेंस मुहिम के परिणामस्वरूप प्रदेश की पंचायतें इस सम्मान को पाने में सफल हो पाई हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए यह बड़े गर्भ की बात है और साथ ही बड़ी उपलब्ध भी है। इस सबका श्रेय प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर को जाता है जिनके मार्गदर्शन में सुशासन के लिए पंचायतों में जीडीएल अपनाया गया है उसे देश भर में सशासन निली है। हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा रहा है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में कुशलता, पारदर्शिता तथा दक्षता लाने के प्रयास कर रही है। ई-पंचायत के माध्यम से प्रदेश में जन्म मृत्यु पंजीकरण सहित आय व्यय का लेखा-जोखा आदि सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। प्रदेश में नव गठित 412 पंचायतों को छोड़ कर सभी पंचायतों को इंटरनेट के साथ जोड़ा जाएगा। शेष पंचायतों को भी शीघ्र ही इंटरनेट सुविधा के साथ जोड़ा जाएगा। जन्म व मृत्यु पंजीकरण को लोक सेवा गांधी अधिनियम के दायरे में रखा गया है। इसमें निर्धारित अवधि के भीतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यही नहीं मनरेखा के तहत होने वाले कार्यों को भी ऑनलाइन श्रेणी में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने पंचायती राज विभाग को ई-पंचायत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करने के लिए बधाई दी। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार पंचायतों को और सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है और 15वें वित्तायोग ने पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 1600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं और करीब 200 करोड़ रुपये की राशि पंचायतों को जारी भी कर दी गई है। ई-गवर्नेंस प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन का ही नीतीजा है कि इससे प्रदेश सरकार को सारे आँकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जिससे सरकारों को विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाने के लिए मदद मिलती है। इसके परिणामस्वरूप एक कॉर्मन डाटा टेयर हो जाता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इससे जनता और सरकार के बीच स्वस्थ एवं पारदर्शी संवाद को मजबूत बनाया जा सकता है। ई-गवर्नेंस का सुशासन, भ्रष्टाचार योजने एवं लोक सेवाओं को आम नागरिकों तक आसानी से पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

कोविड-19 प्रबंधन के लिए चार कमेटियां गठित

(पृष्ठ एक का शेष) सिलेण्डर की आपूर्ति, सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर सभी सात स्थानों पर पीएसएल लांट कार्यशील करने के साथ प्रदेश के उपायुक्तों/मुख्य विकासिता अधिकारियों/ विकासिता अधीक्षकों के साथ डीसीएचएस, डीसीएचसी, डीसीसीसी स्तर पर अतिरिक्त बिस्तरों की क्षमता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाएगी।

कोविड-19 मरीज/एम्बुलेंस प्रबंधन कमेटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एसएसओ डॉ. राजेश ठाकुर को समन्वयक, आईजीएमसी के डॉ. मलय सरकार, डॉ. संजय महाजन व डॉ.डी.एच.एस. के डॉ. पदम नेगी को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी डीसीएच/डीसीएचसी इत्यादि में सभी सुविधाएं, जिला स्तर पर मरीजों को संबंधित अस्पतालों में ले जाने के लिए जिले की टीमों को निर्देश देने के साथ कोविड अस्पतालों में कोविड संबंधित आवश्यक दवाओं जैसे रेमिडिसिवीर की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। वही, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समन्वय कमेटी में शहरी विकास निदेशक अधिकारी इत्यादि द्वारा विकासित सेवाएं के अतिरिक्त निदेशक सुमित रियमटा, स्वास्थ्य निदेशालय के डॉ. रमेश चंद्र को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी अधीक्षित घरानों से कोविड-19 एसडीआरएफ फंड के लिए सभी संभावित दानकर्ताओं से अंशदान दिलाने का प्रयास करेगी। कमेटी प्रदेश के कोविड अस्पतालों में संसाधनों के मध्य दूरी को कम करके कोविड-19 अस्पतालों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

यह कमेटी अंशदान में मिली सामग्री विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। मीडिया/आईईसी कमेटी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के मिशन निदेशक डॉ. निपुण जिंदल को समन्वयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप ग्रन्थीर अस्पतालों में कोविड संबंधित आवश्यक दवाओं जैसे रेमिडिसिवीर की आपूर्ति विकासित करेगी। वही, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समन्वय कमेटी में शहरी विकास निदेशक अधिकारी इत्यादि द्वारा विकासित सेवाएं के अतिरिक्त निदेशक सुमित रियमटा, स्वास्थ्य निदेशालय के डॉ. रमेश चंद्र को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी अधीक्षित घरानों से कोविड-19 एसडीआरएफ फंड के लिए सभी संभावित दानकर्ताओं से अंशदान दिलाने का प्रयास करेगी। कमेटी प्रदेश के कोविड अस्पतालों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

पंचायतों के काम-काज पर केन्द्र सरकार की मोहर

(पृष्ठ एक का शेष) प्रशासनिक कार्यों में दक्षता एवं गुणवत्ता लाने के लिए राज्य में आरंभ की गई ई-गवर्नेंस मुहिम के परिणामस्वरूप प्रदेश की पंचायतें इस सम्मान को पाने में सफल हो पाई हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए यह बड़े गर्भ की बात है और साथ ही बड़ी उपलब्ध भी है। इस सबका श्रेय प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर को जाता है जिनके मार्गदर्शन में सुशासन के लिए पंचायतों में जीडीएल अपनाया गया है उसे देश भर में सशासन निली है। हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा रहा है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में कुशलता, पारदर्शिता तथा दक्षता लाने के प्रयास कर रही है। ई-पंचायत के माध्यम से प्रदेश में जन्म मृत्यु पंजीकरण सहित आय व्यय का लेखा-जोखा आदि सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। प्रदेश में नव गठित 412 पंचायतों को छोड़ कर सभी पंचायतों को इंटरनेट के साथ जोड़ा जाएगा। शेष पंचायतों को भी शीघ्र ही इंटरनेट सुविधा के साथ जोड़ा जाएगा। जन्म व मृत्यु पंजीकरण को लोक सेवा गांधी अधिनियम के दायरे में रखा गया है। इसमें निर्धारित अवधि के भीतर स

कोविड लड़ाई में पूर्व सैनिकों की सेवाएं ले हिमाचल

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गत दिनों राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय से दूरभाष पर बातचीत कर कोविड-19 को लेकर राज्य की स्थिति और सुविधाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ लेने का सुझाव दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक हैं और यहां कई प्रकार से सैनिक व्यवस्था भी उपलब्ध है। यह दौर महामारी का है। इसलिए, इस दौरान राज्य को अपने पूर्व सैनिकों की सेवाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिक गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस व अन्य मेडिकल सुविधाओं का भी लाभ लिया जा सकता है।

श्री सिंह ने महामारी के खिलाफ प्रदेश स्तर पर किए जा रहे विभिन्न प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मिलकर इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए।

राज्यपाल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा हिमाचल के प्रति व्यक्त उनकी चिंता पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्व सैनिकों और सैन्य व्यवस्था के बेतवार्क इस दिशा में पहले से ही क्रियाशील है, जिसका लाभ और प्रभावी तरीके से लिया जाएगा ताकि इस लड़ाई में विजय हासिल की जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके सुझावों पर कार्य योजना बनाकर महामारी के खिलाफ क्षेत्रीय स्तर पर पूर्व सैनिकों की अधिक से अधिक सेवाओं को लेकर मजबूती से काम किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री की राज्य के प्रति संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त किया।

आगजनी प्रभावित परिवारों को श्रेष्ठी राहत सामग्री

राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने जिला शिमला के कोटाहाई क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर पंचायत के फैलै गंग में आग की घटना पर दुर्ख व्यक्त किया है जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई और लगभग छह परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्यपाल जो राज्य डेक्रॉस के अध्यक्ष भी हैं, वे फौरी राहत के तौर पर प्रभावित परिवारों को राज्य डेक्रॉस की ओर से कंबल, तिरपाल, किंचन सैट और सैनिकेशन किट्स आदि भेजे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

उचित मूल्य की दुकानों की समय सारणी जारी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने गत दिनों शिमला में बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में रविवार को कार्य समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक और सर्दियों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक होगा। उचित मूल्यों की दुकानें हर सोमवार को बद्द रहेंगी तथा दुकान धारक को दुकान परिसर में यह समय सारणी जारी की जा रुकी है। उन्होंने बताया कि उचित मूल्यों की दुकानें प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तथा दोपहर 2:00 बजे से

सायं 5:00 बजे तक खुली रहेंगी। दोपहर के भोजन का समय 1:00 बजे 2:00 बजे तक होगा। ग्रीष्मकाल में रविवार को कार्य समय प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक होगा। उचित मूल्यों की दुकानें हर सोमवार को बद्द रहेंगी तथा दुकान धारक को दुकान परिसर में यह समय सारणी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी।

प्रधानमंत्री अन्न योजना

से 28.64 लाख

उपभोक्ता लाभान्वित

खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजिन्द्र गर्ग ने गत दिनों शिमला में बताया कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अन्तर्गत चयनित अन्तर्दोष अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक गृहस्थियां जिनमें बीपीएल, अन्नपूर्णा, एकल नारी, तिक्कियन परिवार शामिल हैं, को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत मई व जून, 2021 के लिए पांच किलोग्राम खाद्यावल्प प्रति लाभार्थी (तीन कि.ग्रा. गंदम व दो कि.ग्रा. चावल) निःशुल्क वितरित करेंगी।

श्री राजिन्द्र गर्ग ने बताया कि प्रदेश को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत कुल 16822.950 मीट्रिक टन गंदम व 11821.610 मीट्रिक टन चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 28.64 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उपभोक्ता को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर ने गत दिनों धर्मशाला में जिला कांगड़ा में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करके अध्यक्षता करते हुए कहा कि राधास्वामी परिसर, परौर को हिमाचल बिस्तरों तक की क्षमता वाले अस्थायी अस्पताल में परिवर्तित कर इसे क्रियाशील बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में किंशुल्क वितरित करेंगी। उन्होंने कहा कि गंदम व एकल नारी, तिक्कियन परिवार शामिल हैं। इसके अलावा, प्रदेश में ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य राज्य में किंशी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि गंदम व में 50 बिस्तरों वाले सिटी सेंटर में अस्पताल को शीघ्र कोविड-19 रोगियों के लिए क्रियाशील बना दिया जाएगा।

श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोविड मामलों में तीव्र वृद्धि

के दृष्टिगत सरकार ने राज्य के चार सीमावर्ती जिलों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक कोरोना कार्पूर्स लगाने का निर्णय लिया है। बाहर से प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों से 72 घण्टे पहले किए गए आरटीपीसीआर परीक्षण की रिपोर्ट साथ लाने और 14 दिनों की अवधि के लिए अपने निवास स्थान पर होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं

नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार द्वारा विवाह समारोह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया।

इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने डा. राजीव गांधी राजकीय राजनीतिकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय परिवेश की दैरा किया। उन्होंने कहा कि इस आयुर्वेदिक महाविद्यालय के नवगिरिमित भवन में कोविड-19 रोगियों के लिए अतिरिक्त 50 बिस्तरों की सुविधा सृजित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अस्पताल में बिस्तरों की क्षमता 100 तक बढ़ाई जाए।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरावी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैनल, सांसद किशन कपूर, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति और पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

गगल में शुरू हुआ 50 बिस्तरों वाला मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल

और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से बाहरी राज्यों से आगे वाले लोगों की निगरानी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी मरीजों और होम आइसोलेशन में रह रहे उनके परिजनों को इस वायरस से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना चाहिए। डाक्टरों को होम आइसोलेशन रोगियों के स्वास्थ्य मापदण्डों की

कोलोनियों के प्रतिनिधियों को भी बीमाकाल में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक कोरोना कार्पूर्स लगाने का निर्णय लिया है। बाहर से प्रदेश में आपरेशन देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के एक ग्राम प्रवक्ता ने गत दिनों शिमला में बताया कि प्रदेश में अन्तर्गत लड़ाई में राज्य के अन्तर्गत लड़ाई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार को बुक्सान की तरफ से अस्पताल के अंकलन की वीडियोग्राफी सहित विस्तृत रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर भेजी जाए।

बागबानी मंत्री ने निर्देश दिए कि संबंधित क्षेत्रों के उपमण्डलाधिकारी इस कार्य की दैनिक समीक्षा रिपोर्ट भी बीमाकालीन मंत्री के कार्यालय में भेजे। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग ने प्रदेश के बागबानों को पौध संरक्षण दवाइयों के अनुदान को सीधे किसानों व बागबानों के बैंक खातों में वितरित करने का निर्णय लिया है।

श्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने

के लिए निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार द्वारा विवाह समारोह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया।

प्रवक्ता ने कहा कि कोविड

टीकाकरण के देखते हुए लोगों से तीसरे चरण में टीकाकरण के लिए अधिक से अधिक संख्या में आगे आगे की मांग की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी कोविड टीकाकरण केब्डों पर टीका लगाने के लिए राज्य ने सीरम इंस्ट्रिक्यूट ऑफ इंडिया से कोविड की 73 लाख खुराकें किए। इन्हें विव